

अत्यावश्यक

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

मुख्यालय जयपुर - 302001


यूओओ नोट

विषय:- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत लगभग 10161 अधिकारियों/ कर्मचारियों का सामुहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी लिये जाने के लिए निविदा सूचना निगम वेबसाइट, ई प्रोक्योरमेंट एवं SPPP पोर्टल पर उपलब्ध करवाये जाने के क्रम में।

विषयान्तर्गत लेख है, कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत लगभग 10161 अधिकारियों/ कर्मचारियों की सामुहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी (अनुमानित लागत लगभग 24 लाख रु) लिये जाने हेतु ई - बोली आमंत्रण दस्तावेज संलग्न कर भिजवाए जा रहे हैं।

कृपया अविलम्ब निगम वेबसाइट, ई प्रोक्योरमेंट तथा SPPP पोर्टल पर प्रकाशन/अपलोड करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


वित्तीय सलाहकार

उप महाप्रबन्धक (आईटी/सांख्यिकी)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन

मुख्यालय जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक एफ-4/वित्त/भुगतान-1/2025/ 3143

दिनांक 31/07/25

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निगम में नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी वर्ष 2025-26

ई-बोली सूचना संख्या:-एफ 4/मुख्या/वित्त/भु0/2025/01

दिनांक:-31/7/25

ई-बोली सूचना संख्या 2025-26/01

क्र- सं.	कार्य का विवरण	पात्रता	कार्य की अनुमानित लागत	बोली सुरक्षा राशि	बोली प्रपत्र की लागत	बोली प्रोसेसिंग फीस	
1	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निगम में नियुक्त कर्मचारी/ अधिकारियों (लगभग 10161) की सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी राशि 5 लाख प्रति कर्मचारी	आई0आर0डी0ए0 द्वारा भारत में सामूहिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय हेतु अधिकृत कम्पनियाँ ही भाग ले सकती हैं।	24 लाख	48000 रु (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)	500रु	1000रु	बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि /समय 17.07.2025 / 15:00 बजे तक टेक्निकल बिड खोलने की तिथि/समय 18.07.25 / 11:00 बजे तक फाईनेशियल बिड खोलने की तिथि/समय 21.07.2025 / 16:00 बजे तक

टेन्डर की शर्तें

1. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
2. बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय बोलियां खोली जावेगी।
3. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाकर अथवा e-procurement cell RISL, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर से यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। (इस कार्य हेतु हैल्प डेस्क नंबर 0120-4200462, 0120-4001002, 91-8826246593 पर समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 तक कार्य दिवसों में सम्पर्क किया जा सकता है इसके अतिरिक्त समस्त कार्य दिवसों यथा सोमवार से शुक्रवार को समय प्रातः 09.30 बजे से 06.00 बजे तक स्थानीय दूरभाष नंबर 0141-4022688) पर सम्पर्क किया जा सकता है। इस संबंध में हैल्प डेस्क के ई-मेल आईडी Support-eproc@nic.in पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
4. बोली प्रपत्रों में बोलीदाता के लिए सूचना एवं पात्रता आदि की शर्तें, बोली प्रपत्र के साथ <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है तथा ऑन लाईन ई-बोली <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर ही प्रस्तुत की जानी है। बोली सूचना में किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन/सुधार की स्थिति में सूचना <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर प्रकाशित की जावेगी।
5. बोली प्रस्तुत करते समय बोलीदाता को कार्य की अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत सुरक्षा राशि की डीडी (Financial advisor RSRTC, Jaipur) के नाम से प्रस्तुत करनी होगी तथा बोली प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर कार्य/बीमा की वार्षिक लागत की 5 प्रतिशत राशि परफोरमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में जरिये डीडी बैंक गारण्टी जमा करानी आवश्यक होगी। किन्तु केन्द्र/राज्य के अधीन संचालित बीमा कम्पनियों को बोली सुरक्षा राशि एवं कार्य सम्पन्न सुरक्षा राशि के संबंध में बोली के साथ हस्ताक्षरयुक्त घोषणा-पत्र (प्रपत्र अ) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति, बारंटी बाध्यताओं और रख रखाव एवं दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे 180 दिनों (6 माह) की कालावधि के लिए विधिमान्य होनी चाहिए। यदि किसी अनुबन्ध की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति की विधिमान्यता की अवधि भी उसी अनुसार बढ़ाई जायेगी।

7. कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई बैंक गारण्टी के सत्यापित नहीं होने की स्थिति में बोली लगाने वाली संस्था को राजस्थान लोक उपादन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 11 (Code of Integrity for procuring entity and bidder) एवं धारा 46 (Debarment from Bidding) के अन्तर्गत बोली लगाने से विवर्जित किया जायेगा।
8. अपूर्ण एवं सशर्त बोली प्रपत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
9. बोली प्रपत्र में आवेदन करते समय, बोली-प्रपत्र शुल्क राशि 500/-रुपये की डी0डी0 Financial advisor RSRTC, Jaipur एवं बोली प्रोसेसिंग शुल्क राशि 1000 /- MD RISL, Jaipur के पक्ष में दिनांक 16.07.2025 तक जमा करवा कर, डी.डी संख्या एवं बैंक का नाम व ब्रॉन्च इत्यादि का विवरण अंकित करें। तथा बोलीदाता को उक्त देय डी0डी0 की फोटो प्रतियां ऑन लाईन बोली के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। कोई भी बोली इलैक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. ऑन लाईन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रॉनिक बोली में साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डी.एस.सी. (D.S.C) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
11. बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
12. इलैक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।

13. **Dispute Resolution:** Any Dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order no. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

14. ऑनलाईन बोलियां निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी।
15. बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करावें। बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई जानकारी/दस्तावेज को निगम स्तर पर सत्यापन का अधिकार सुरक्षित है।
16. तकनीकी एवं वित्तीय बोलियां अलग-अलग खोली जावेगी। इसलिए दोनों बोलियां अलग-अलग ऑनलाईन भरी जावेगी। तकनीकी रूप में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियां खोली जावेगी अन्य बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
17. वर्तमान में निगम में ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 10161 है, जो कि घट/बढ़ सकती है।
18. जिन कर्मचारियों की सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी ली जानी है, उनका बीमा परिलाभ राशि रु 5,00,000/- प्रति कर्मचारी होगा।
19. यह पॉलिसी लिये जाने की दिनांक से एक साल तक लागू मानी जायेगी। जिसे आपसी सहमति से आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
20. किसी भी कर्मचारी का सामूहिक दुर्घटना बीमा दावा Time Barred नहीं माना जायेगा।
21. भुगतान दावेदार द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते में/चैक के माध्यम से करना होगा।
22. प्रस्तावक कंपनी का स्थानीय कार्यालय जयपुर में होना आवश्यक है।
23. कम्पनी पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी, मण्डल, निगम या बोर्ड में ग्रुप बीमा करने का अनुभव होना चाहिए।
24. सफल कंपनी से एमओयू कराया जायेगा जिसकी शर्तें घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती हैं।
25. इस अनुबंध से संबंधित किसी भी दावे के निष्पादन में होने वाले विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
26. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये सेवाकर या अन्य किसी प्रकार के करों का दायित्व कम्पनी का होगा, अर्थात् कर वंचना का दायित्व कंपनी का होगा।
27. टेण्डर सशर्त स्वीकार नहीं किया जावेगा।
28. किसी भी टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार निगम का होगा।

वित्तीय सलाहकार

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निगम में नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की सामूहिक
दुर्घटना बीमा पॉलिसी

वर्ष 2025-2026

वित्तीय सलाहकार
राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय,
परिवहन मार्ग चौमू हाउस,
जयपुर 302001

विषय:- राजस्थान परिवहन निगम में नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की सामूहिक दुर्घटना
बीमा पॉलिसी वर्ष 2025-2026 करने हेतु जारी बोली प्रपत्र की शर्तें ।
संदर्भ:- बोली सूचना संख्या:-एफ 4/मुख्या/वित्त/भु0/ दिनांक

1. हम यह घोषणा करते हैं कि हमारी बीमा कम्पनी बोली की समस्त पात्रता एवं योग्यतायें पूर्ण करती है तथा निगम द्वारा वांछित बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु अधिकृत है।
2. हमारे द्वारा बोली प्रपत्रों को भलि-भांति पढ़ लिया गया है।
3. हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली प्रस्ताव, बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक से 120 दिवस हेतु मान्य होंगे, जो बोली प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की स्थिति में बोली की शर्तानुसार अवधि के लिए मान्य होंगे।
4. हमारे प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किये जाने की स्थिति में निगम द्वारा जारी आदेशानुसार निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पॉलिसी वर्ष 2025-2026 करने तथा इस हेतु निगम द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करने हेतु स्वीकृति देते हैं।
5. हमारी फर्म/कम्पनी भारत में बीमा व्यवसाय करने हेतु आई0आर0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत की हुई है, जिसका मान्य प्रमाण पत्र सलग्न है।
6. हमारी कम्पनी उक्त बोली के तहत प्रस्ताव सीधे कम्पनी की ओर से प्रस्तुत कर रही है, जिसमें कोई ब्रोकर सम्मिलित नहीं है।
7. हमारी कम्पनी को केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं किया हुआ है।
8. हमारी कम्पनी को ज्ञात है कि निगम सर्वाधिक कम दर प्रस्तावकर्ता कम्पनी को बीमा पॉलिसी करने हेतु अधिकृत करने हेतु बाध्य नहीं है।

पूरा नाम:-

हैसियत:- मालिक/पार्टनर

पूर्ण पता:-

घोषणा-पत्र

बोलीदाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर डिजिटल हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

- 1 मैं/हम बोली प्रपत्र शुल्क की राशि जमा रुपये 500/-डी.डी. संख्या-----
दिनांक----- बोली प्रोसेसिंग शुल्क राशि 1000 /- डी.डी. संख्या-----
दिनांक-----एवं बोली प्रतिभूति राशि ----- रुपये की डी.डी संख्या
-----दिनांक----- संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
- 2 मैं/हमने निगम की समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ दिये गये प्रारूप आधार पर अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर कर दूँगा/देगें।
- 3 मैं/हम घोषणा करता/करते हैं/हूँ कि मैंने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उसमें किसी अन्य संस्था को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की तरफ से नहीं दिये गये है।
- 4 मैं/हम वचन देता/देते है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव बोली खोलने की दिनांक से 120 की अवधि तक लागू रहेगा।

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर-बोलीदाता

मय पद/हैसियत व मोहर सहित

सामूहिक दुर्घटना बीमा के देय बीमा लाभ का विवरण

बीमा अवधि के दौरान निगम कर्मचारी की मृत्यु/दुर्घटना ग्रस्त होने पर नीचे उल्लेखित स्थिति में उनके सामने अंकितानुसार बीमा लाभ का भुगतान किया जायेगा।

क्र०स	दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार	देय बीमा धन (रूपये में)
1.	दुर्घटना में मृत्यु होने/पूर्ण रूपेण स्थाई अपंगता/दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आँखें पूर्ण रूपेण भंग होने पर	5.00 लाख
2.	दुर्घटना के कारण एक आँख, एक पैर या एक हाथ पूर्ण रूपेण भंग होने पर	2.50 लाख
3.	आंशिक विकलांगता/क्षति की दशा में 1. पोंवों की अंगुलियों की हानि सभी बड़ी अंगुलियास्थ बड़ी दोनों अंगुलियास्थ बड़ी एक अंगुलियास्थ बड़ी के अतिरिक्त यदि प्रत्येक के एक से अधिक हानि हो 2. दोनों कानों से श्रवण शक्ति की हानि 3. एक कान से श्रवण शक्ति की हानि 4. एक हाथ की चार अंगुलियों व अँगूठे की हानि 5. चारों अंगुलियों की हानि 6. अँगूठे की हानि दोनों अंगुलियास्थ या एक अंगुलियास्थ 7. तर्जनी की हानि तीन/दो/एक अंगुलियास्थ 8. मध्यमा की हानि तीन/दो/एक अंगुलियास्थ 9. अनामिका की हानि तीन/दो/एक अंगुलियास्थ 10. कनिष्ठा की हानि तीन/दो/एक अंगुलियास्थ 11. करपास्थियों की हानि प्रथम, द्वितीय,द्वितीय (अतिरिक्त) तृतीय,चतुर्थ एवं पंचम (अतिरिक्त) 12. अन्य कोई स्थाई आंशिक अशक्तता	पूँजीगत राशि का प्रतिशत 20 05 02 01 50 15 40 35 25/10 10/8/4 6/4/2 5/4/2 4/3/2 3/2 चिकित्सक द्वारा निर्धारित अनुसार प्रतिशत
4	मृत्यु की दशा में शव को लाने ले जाने पर खर्च राशि	दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति के शव को दुर्घटना स्थल/अस्पताल से उसके पैतृक गांव तक परिवहन का पुनर्भरण अथवा एक हजार पाँच सौ रुपये, जो भी कम होगा देय होगा।

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. बीमा कम्पनी का नाम
2. प्रधान कार्यालय का पता
3. कम्पनी के जयपुर कार्यालय की शाखा का पता
4. ई – मेल..... फोन नं.
5. आई. आर. डी. ए. के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक

नोट:- 1. कम्पनी पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी, मण्डल, निगम या बोर्ड में ग्रुप बीमा करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।
2. कम्पनी का कार्यालय जयपुर में स्थित होना आवश्यक है।

कम्पनी द्वारा अधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर एवं पूरा नाम मय सील

वित्तीय बोली(ऑनलाईन BOQ में प्रस्तुत की जावें)

बीमा कम्पनी का नाम एवं पता :

बीमा कम्पनी का मुख्य कार्यालय का पता :

क्रम स०	विवरण	बीमा प्रीमियम राशि प्रति कर्मचारी	
		राशि रु० अंको में	राशि रु० शब्दों में
1.	सामुहिक दुर्घटना बीमा प्रीमियम की दर प्रति कर्मचारी (देय बीमा लाभो पर)समस्त करें सहित	ऑनलाईन BOQ में प्रस्तुत की जावें	

कम्पनी द्वारा अधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर एवं पूरा नाम मय सील

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- a. Have controlling partners/shareholders in common; or
- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
- d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement of in
response to their Notice Inviting Bids No.....Dated I/We hereby
declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding Document, which material affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation: Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is HOD, Procuring Entity.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Managing Director, RSRTC .

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2.The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect document, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,
2012

Appeal Noof.....

Before the..... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii). Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities.

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.